पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : क्या माननीय सदस्य स्टाक की कमी के बारे में पूछ रहे हैं ?—जहां तक गोरखपुर का ताल्लुक है, उसमें 1967-68 और 1968-69 में तो स्टाक में कोई कमी नहीं थी। 1969-70 में वहां कोई साढ़े आठ लाख रुपये का माल स्टाक में कम बताया गया है और इस साल भी करीब 4,514 टन की स्टाक में कमी बताई गई है, जिसकी टोटल लागत 25.5 लाख रुपये के करीब है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंडि : गोरखपुर उर्वरक कारखाने का जब निर्माण हुआ उस समय यह विचार था कि इसके निर्माण में पूर्वांचल के लोगों की भर्ती अधिक संख्या में होगी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। क्या अब जब कारखाने का विस्तार होगा उसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल भाग के लोगों की संख्या पर ध्यान दिया जाएगा अथवा नहीं ?

श्री पी० सी० सेठी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भर्ती का ताल्लुक है होम मिनिस्ट्री के सर्कुलर के मुताबिक भर्ती करने के लिये सब फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज और कोरपोरेशन को पहले भी लिखा गया था, फिर से उनको इसकी याददाश्त दिलाई गई कि इस सर्कुलर के अनुसार क्लास 3 और 4 के सब ऐजप्लाईज स्थानीय होने चाहिये। बाकी आल इंडिया सेलेक्शन पोस्ट्स जो हैं उनका सेलेक्शन आल इण्डिया मैरिट पर होता है। यदि होम मिनिस्ट्री के उस सर्कुलर का पालन नहीं हुआ है तो माननीय सदस्य मुझे जानकारी देंगे तो मैं उस सम्बन्ध में छानबीन करूंगा और आइन्दा भर्ती के संबंध में इस को सख्ती से पालन करने की कोशिश की जायगी।

श्री नाथूराम अहिरवार : मन्त्री जी ने बताया कि गृह मन्त्रालय को इस बात के लिए लिखा गया है कि फर्टिलाइजर कारपोरेशन के जितने कारखाने हैं उनमें क्लास 3 और 4 के ऐमप्लाईज स्थानीय होने चाहियें। तो क्या यह भारत के पूरे पब्लिक अन्डरटेकिंग्स के लिए लागू है ?

श्री पी० सी० सेठी : गृह मन्त्रालय को नहीं लिखा गया बल्कि गृह मन्त्रालय के आदेश के मुताबिक सब फैक्ट्रीज को आदेश दिए गए हैं कि इन का पूरी तौर पर पालन किया जाय।

श्री सतपाल कपूर : क्या मन्त्री जी रोशनी डालेंगे कि जैसे 35 लाख रु० की कमी गोरखपुर फैक्ट्री के स्टाक में हुई, इस तरह से और भी फैक्ट्रीज हैं जिन के स्टाक में पिछले दो, तीन सालों में कमी हुई है ?

श्री पी० सी सेठी : ट्रोम्बे में 1967-68 में साढ़े पांच लाख की कमी हुई, 1968-69 में 3 लाख 64 हजार की और 1969-70 में 46 लाख की।

श्री सतपाल कपूर : स्पीकर साहब अभी-अभी इन्होंने यहां ऐडमिट किया है कि कमी हुई है तो इस कमी की आप ने किस पर जिम्मेदारी डाली है ? या राइट आफ कर दिया ?

अध्यक्ष महोदय : आप ने सूचना मांगी थी, बहस नहीं मांगी। क्वेश्चन आवर में तो सूचना होती है।

Proposals for Revision of Pay Scales of Defence Services Personnel

\+

*1208. SHRI RAMSHEKHAR PRASAD SINGH :
SHRI P. GANGADEB :

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether the proposals made by the Chief of the Army Staff for the revision of pay scales and better service conditions of Army personnel have also been proposed by the Chiefs of the Naval and the Air Staff ;

(b) if so, whether they have also expressed adverse service conditions under which they have to work ;

(c) whether uniformity of pay scales have been suggested by the Services Chiefs ; and

(d) if so, how far the suggested service conditions have been agreed to ?

THE MINISTER OF STATE (DEFENCE PRODUCTION) IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) An Expert Cell comprising three senior Service experts from the three Services, coordinated and scrutinised the proposals submitted by the Services Headquarters after considering the reports made by the various Commands of Army, Navy and Air Force. The Expert Cell examined them under the guidance and direction of the Chief of the Army Staff, Chief of the Naval Staff and Chief of the Air Staff and jointly evolved proposals for revision of pay scales for consideration by the Pay Commission.

No suggestion regarding service conditions has been made.

(b) Yes, Sir

(c) In suggesting the pay scales the need to have the maximum possible uniformity in the pay scales in the three Services have been kept in view.

(d) The proposals regarding pay scales etc. have been submitted to the Pay Commission. The Pay Commission will be taking these proposals into account while formulating their recommendations.

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : मन्त्री महोदय के खंड (बी)के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जो लोग फौज में काम करते हैं उन्हीं लोगों की सर्विस कंडीशन खराब हैं, और इसके विषय में कोई मेमोरेन्डम मिनिस्ट्री में या आर्मी के बड़े अफसरों को पहुँचा है और उस पर विचार नहीं हुआ है। तो उसके बारे में कोई गौर करने की बात है उनकी सर्विस कंडीशन्स को इमप्रुव करने के लिए ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जो हमारी रक्षा सेनाओं में काम करने वाले लोग हैं उनके जो काम करने के तरीके हैं और जिन विभिन्न परिस्थितियों में उन्हें काम करना पड़ता है वे हम सब जानते हैं कि बड़ी कठिन हैं और उन्हे कोई सामान्य परिस्थितियों में काम करने का मौका नहीं मिलता। कभी कभी अधिक ऊंचाई पर जा कर और जंगलों में काम करना पड़ता है जहां पर सड़कें भी नहीं रहतीं। उनके जीवन को दिन रात खतरा बना रहता है। ऐसे अस्त्र-शस्त्र लेकर चलते हैं जिनसे खतरा रहता है। ये सब बातें हमें मालूम हैं और इस तरह से हम उनकी सुरक्षा के लिए या उनको ठीक से रखने के लिए जो भी उपाय कर सकते हैं करते रहते हैं।

तो जैसा मैंने कहा वेतन आयोग इन चीजों के बीच में नहीं जाएगा। इन के लिए तो जो सर्विस हैडक्वार्टर्स हैं वही देख कर जो कुछ वह कर सकते हैं उनकी दशाओं को सुधारने के लिए वही करेंगे। और यह तो बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है कि किस तरह काम उनको समय-समय पर करना पड़ता है। तो ये जो कठिनाइयां हैं ये पे कमीशन को मालूम हैं, उन के सामने पेश की गई है।

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : पे कमीशन की रिपोर्ट कब तक आ जाने की आशा की जाती है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह कहना तो मुश्किल है। इस की सूचना तो वित्त मंत्रालय के पास होगी। फिर भी पिछले पे कमीशनों ने जिस तरह काम किया उसको देखा जाय तो जिस दिन से कमीशन ने काम शुरू किया है उस दिन से दो, सवा दो साल लग सकते हैं। फिर भी इसके सम्बन्ध में कुछ कहना मुश्किल है।

SHRI S. M. BANERJEE : May I know whether the attention of the hon. Minister has been drawn to a press news issued by the Pay Commission that a report might be submitted in the year 1972, and if so, in which month it is going to be submitted or whether it is going to take more time ? I would like to know from the hon Minister whether the armed personnel and

other personnel including some of the civilians in Defence have demanded a second instalment of interim relief in case the Pay Commission's report is not submitted within six months and if so, whether the reaction of his Ministry has been conveyed to the Finance Minister ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : As far as I know, there is no intention on the part of the Government to award any second interim relief to any class of Central Government employees.

SHRI S. M. BANERJEE : He is talking like an ex-Finance Minister.

श्री बी० पी० मौर्य : पाकिस्तान जिसकी नीति भारत के प्रति क्रोध और घृणा की रही है, उसके फौजी लोगों को, खासतौर से थल सेना के सिपाहियों को अच्छा वेतन और ज्यादा अच्छा कपड़ा तथा खाना मिलता है । क्या यह बात रक्षा मन्त्री जी की जानकारी में है ? अगर हां, तो इन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये क्या भारतीय सेना के लोगों को वही तमाम सुविधायें देंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह कहना गलत है कि पाकिस्तान के सैनिकों को अच्छा मिलता है खाना, कपड़ा.....

श्री बी० पी० मौर्य : तनख्वाह आप से ज्यादा है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं यह बात नहीं मानता । हमारे फौजी संतुष्ट हैं और उनकी देख भाल हम अच्छी तरह से करते हैं । यह बात अलग है कि जो उनकी अच्छी स्थिति है उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करें । और उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने का बन्द होना

*1209. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाना गत सितम्बर में बन्द कर दिया गया था ; और

(ख) क्या उक्त कारखाना घाटे में चल रहा था तथा उसे एक गैर-सरकारी कम्पनी को बेच देने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI DALBIR SINGH) : (a) Sindri unit of Fertilizer Corporation of India was not closed. The Bihar State Superphosphate Factory, an undertaking of the Bihar State Industrial Development Corporation, stopped production in September, 1970.

(b) The factory has been incurring losses since 196 -69. Government of Bihar have reported that there is no proposal to sell the factory to a private company and that measures to restart production are under consideration.

डा० लक्ष्मीनारायण पांडे : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सिन्दरी में राजकीय क्षेत्र में एक तरफ कारखाना खुला और साथ-साथ बिहार सरकार ने भी कारखाना खोला । इस कारण दोनों कारखानों को पर्याप्त रूप में कच्चा माल उपलब्ध नहीं हुआ इसी कारण इन कारखानों को बन्द होने की स्थिति में आना पड़ा ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी०सी० सेठी): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है कि इस कारखाने को बिहार सरकार ने जब से इस को लिया हर साल लौस होता रहा । इसकी वजह यह नहीं है कि उस को रा मैटीरियल नहीं मिलता रहा । और इसकी उन्होंने जांच भी करायी है, और फर्टिलाइजर कारपोरेशन को भी कहा है कि इस की जांच भी कर के दें कि किस तरह से इसको मुनाफे में चलाया जा सकता है । जो जांच की गई है उसमें उन्होंने कुछ तरमीमें मशीनों वगैरह में करने का सुझाव दिया है । उसके अनुसार बिहार सरकार कार्य-वाही करने जा रही है ।